

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण: एक वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य*

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के निजीकरण को व्यापक रूप से भारत में लंबित सुधारों के प्रमुख क्षेत्र के रूप में देखा गया है। यह आलेख निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) के सापेक्ष पीएसबी के प्रदर्शन की अनुभवजन्य रूप से जांच करता है। डेटा एनवेलपमेंट एनालिसिस (डीईए) का उपयोग करते हुए, यह पता चलता है कि जहां पीवीबी लाभ अधिकतम करने में अधिक कुशल हैं, वहीं उनके सार्वजनिक क्षेत्र के समकक्षों ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में बेहतर प्रदर्शन किया है। पीवीबी की तुलना में पीएसबी की श्रम लागत दक्षता अधिक है। अनुभवजन्य साक्ष्य यह भी बताते हैं कि पीवीबी की तुलना में पीएसबी का उधार कम चक्रीय है और इस प्रकार पीएसबी प्रतिचक्रीय मौद्रिक नीति कार्रवाई को गति प्राप्त करने में मदद करते हैं।

भूमिका

1990 के दशक से निजीकरण दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है और पिछले चार दशकों में दुनिया भर की सरकारों ने या तो भागीदारी कम कर दी है या गतिविधियों की एक श्रृंखला से पूरी तरह से पीछे हट गई है। वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) से पहले, बैंकिंग इस प्रवृत्ति का अपवाद नहीं थी। विकासशील देशों में, सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों की आस्ति का औसत हिस्सा 1995 में 40 प्रतिशत से घटकर 2008 में 17 प्रतिशत हो गया, जबकि उच्च आय वाले देशों में यह 1995 में 36 प्रतिशत से गिरकर 2008 में 10 प्रतिशत हो गया। हालांकि, जीएफसी के बाद, बैंकों के सार्वजनिक स्वामित्व में नए सिरे से दिलचस्पी पैदा हुई है क्योंकि कई उच्च आय वाले और विकासशील देशों ने दबावग्रस्त बैंकों को पूंजीकृत या राष्ट्रीयकृत किया। आइसलैंड, कजाकिस्तान, यूनाइटेड किंगडम और रिपब्लिका बोलिवेरियन डे वेनेजुएला जैसे देशों में, बैंकिंग क्षेत्र में सरकार द्वारा धारित आस्तियों का हिस्सा 2008 और 2010 के बीच 10 प्रतिशत के

* यह आलेख बैंकिंग अनुसंधान प्रभाग, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक के स्नेहल एस हेरवाडकर, सोनाली गोयल और रिशुका बंसल द्वारा तैयार किया गया है। इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

बिंदु से भी अधिक बढ़ गया (कल, पेरिया और वेरियर, 2018)। तब से, बैंकों के सार्वजनिक स्वामित्व का पक्ष और विपक्ष पूरी दुनिया में एक गरमागरम बहस का विषय बना हुआ है।

भारत में भी आर्थिक सोच पर निजीकरण का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, हालांकि अब तक बैंकिंग पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा है। केंद्रीय बजट 2021-22 में, सरकार ने दो पीएसबी के निजीकरण की मंशा की घोषणा की। भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर सभी पीएसबी के निजीकरण के लिए मामला बनाने के लिए हाल ही के एक नीतिगत नुस्खे में जोर दिया गया है कि '...पीएसबी ने अर्थव्यवस्था और उनके हितधारकों को कम सेवा दी है', (गुप्ता और पनगढ़िया, 2022)।

यह आलेख साहित्य के उन पहलुओं से प्रेरणा लेकर एक वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है जो कई आधारों पर पीएसबी की भूमिका को सही ठहराते हैं। एटकिंसन और स्टिग्लिट्ज (1980) द्वारा प्रचारित 'सामाजिक दृष्टिकोण' बताते हैं कि सरकारी स्वामित्व वाले उद्यम (एसओई) बाजार की विफलताओं को दूर करने के लिए बनाए गए हैं, और अक्सर उनके सामाजिक लाभ सामाजिक लागतों से अधिक होते हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार, सरकारी स्वामित्व वाले बैंक आर्थिक विकास में योगदान करते हैं और सामान्य आर्थिक कल्याण में सुधार करते हैं (स्टिग्लिट्ज, 1993)। साहित्य के एक अन्य सूत्र से पता चलता है कि सरकार के स्वामित्व वाले बैंकों द्वारा ऋण देना या तो प्रतिचक्रीय है या निजी बैंकों द्वारा उधार देने की तुलना में कम अनुचक्रीय है, विशेष रूप से उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में और इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक समष्टि आर्थिक स्थिरता में योगदान करते हैं (पनिज़ा, 2022; माइको और पनिज़ा) 2006)। विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने निम्न-कार्बन उद्योगों में वित्तीय निवेश को उत्प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे ब्राजील, चीन, जर्मनी, जापान और यूरोपीय संघ जैसे देशों में हरित संक्रमण को बढ़ावा मिला है (मेजुकाटो और पेन्ना, 2016 और शापिरो, 2012)।

एक महत्वपूर्ण पहलू जिसे अक्सर निजीकरण का प्रस्ताव करने वाले शोधकर्ताओं द्वारा अनदेखा किया जाता है, वह वित्तीय समावेशन में पीएसबी द्वारा निभाई गई भूमिका है। उद्देश्य कार्य में इस आयाम को शामिल करते हुए, यह आलेख इस बात का

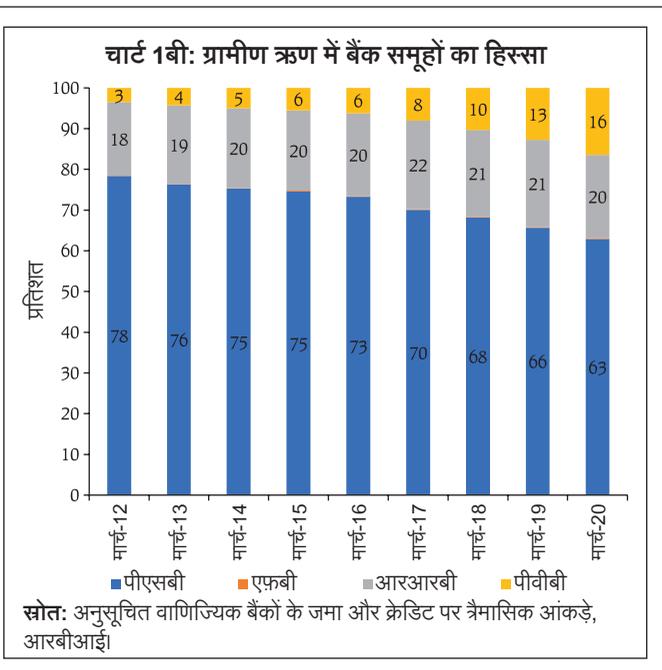
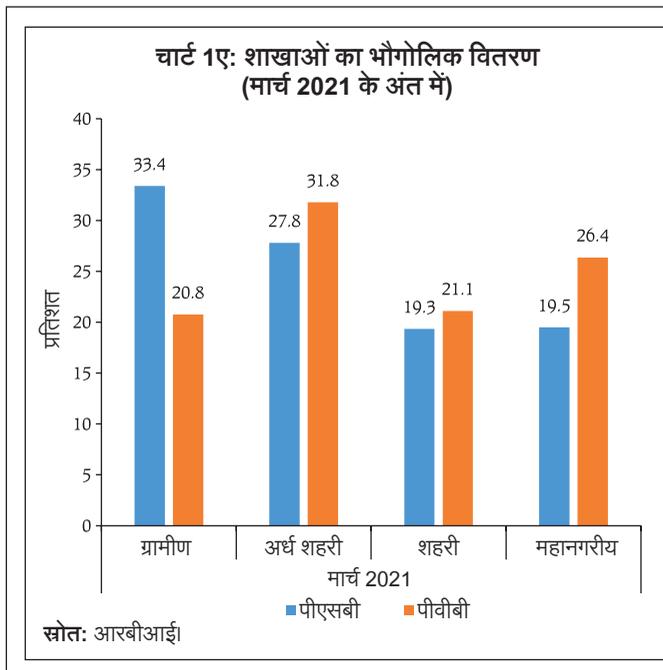
अनुभवजन्य साक्ष्य प्रदान करता है कि किस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारत में अपने निजी क्षेत्र के समकक्षों की तुलना में अधिक कल्याणकारी वृद्धि कर रहे हैं। इसके अलावा, आलेख अनुभवजन्य रूप से स्थापित करता है कि पीएसबी की तुलना में पीवीबी का उधार अधिक अनु-चक्रीय है और इस प्रकार पीएसबी प्रतिचक्रीय मौद्रिक नीति को कर्षण प्राप्त करने में मदद करते हैं। हाल के शोध के अनुसार, जो बताता है कि 'निजी स्वामित्व अकेले विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में स्वचालित रूप से आर्थिक लाभ उत्पन्न नहीं करता है' और 'निजीकरण के अधिक सतर्क और सूक्ष्म मूल्यांकन की आवश्यकता है' (एस्ट्रिन और पेलेटियर, 2018), यह आलेख निजीकरण के लिए क्रमिक दृष्टिकोण की भी सिफारिश करता है।

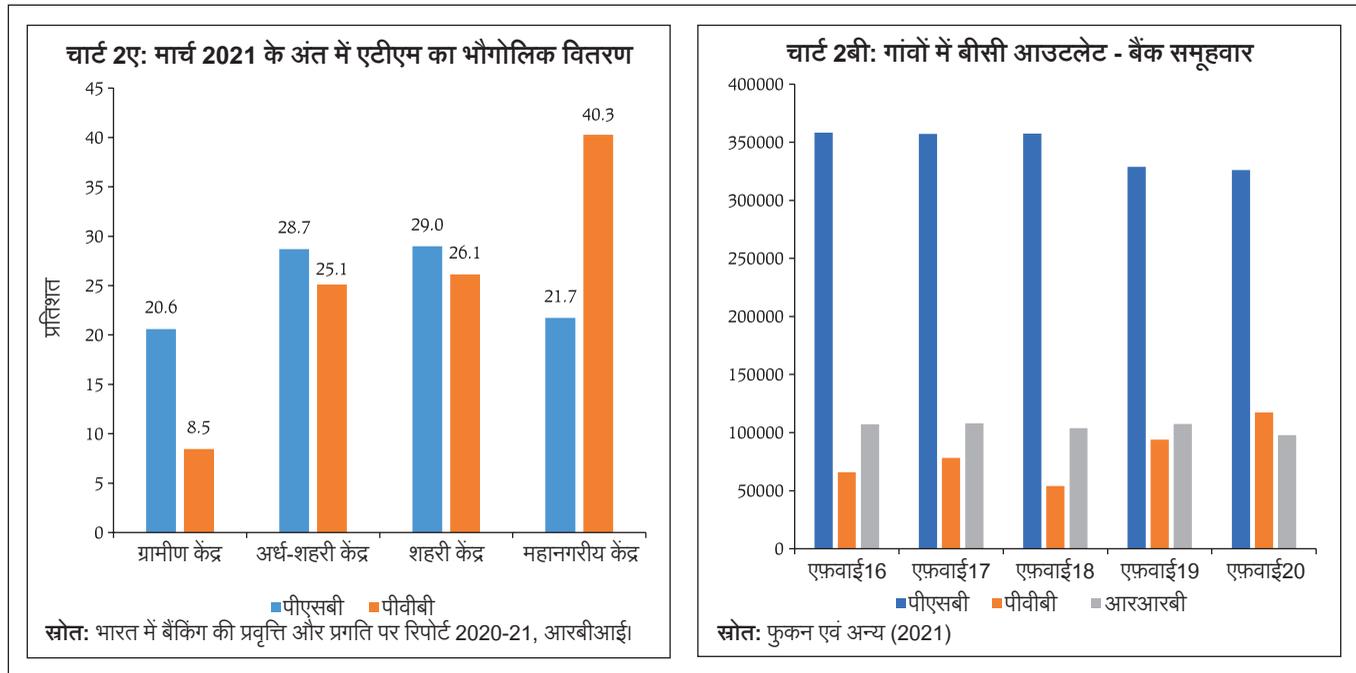
उपरोक्त संदर्भ में, आलेख को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है: खंड II वित्तीय समावेशन में पीएसबी की भूमिका की खोज के लिए समर्पित है। खंड III डीईए का उपयोग करके वैकल्पिक उद्देश्य कार्यों के लिए पीएसबी और पीवीबी का प्रदर्शन मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। खंड IV व्यावसायिक चक्रों की स्थिति के सापेक्ष पीएसबी और पीवीबी के क्रेडिट स्वरूप की जांच करता है। खंड V पीएसबी के प्रदर्शन पर समग्र बाजार प्रतिक्रिया का आकलन करने के लिए नवीनतम डेटा रूझान प्रस्तुत करता है। खंड VI समाप्त होता है और आगे का मार्ग प्रदान करता है।

II. वित्तीय समावेशन में पीएसबी की भूमिका

वित्तीय समावेशन उद्देश्य के प्रति अपनी वचनबद्धता के अनुपालन में पीएसबी की ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं की उच्चतम हिस्सेदारी है, इसके बाद अर्ध-शहरी क्षेत्रों का स्थान है (चार्ट 1ए)। ग्रामीण क्षेत्रों की ऋण मांग को पूरा करने में पीएसबी का दबदबा है (चार्ट 1बी)। हालांकि पीवीबी ग्रामीण इलाकों में कुछ पैठ बना रहे हैं, लेकिन उनकी प्रगति धीमी है।

ईंट और मोटार की शाखाओं को खोलना और उनका रखरखाव करना महंगा है और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में यह आर्थिक रूप से अव्यवहार्य भी हो सकता है,। इसे दूर करने के लिए, पीएसबी ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के नए तरीके अपना रहे हैं। उदाहरण के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में एटीएम में उनकी हिस्सेदारी पीवीबी की तुलना में दोगुनी से अधिक है (चार्ट 2ए)। ग्रामीण और वित्तीय रूप से बहिष्कृत क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए पीएसबी द्वारा एक अन्य चैनल का सबसे प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया है, वह व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल का उपयोग है। ग्रामीण क्षेत्रों में बीसी आउटलेट्स में पीएसबी की हिस्सेदारी इन वर्षों में लगातार 60 प्रतिशत से ऊपर रही है, जो बैंक समूहों में सबसे अधिक है (चार्ट 2बी)। दूसरी ओर पीवीबी ने शहरी बीसी मॉडल को अपनाया है।





प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई), हर घर के लिए कम से कम एक बुनियादी बैंकिंग खाते के साथ बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच की परिकल्पना करती है। जुलाई 2022 तक, 45 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के बैंक खाते खुलवाए गए और इनमें से 78 प्रतिशत खाते पीएसबी में थे (सारणी 1)। इसके अलावा, पीएसबी में खोले गए 60 प्रतिशत से अधिक पीएमजेडीवाई खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में थे।

सारणी 1: बैंक-समूह स्तर पर पीएमजेडीवाई लाभार्थियों का वितरण

(लाभार्थियों की संख्या करोड़ में)

बैंक का प्रकार	ग्रामीण/अर्ध-शहरी केंद्र की बैंक शाखाओं में लाभार्थियों की संख्या	शहरी मेट्रो केंद्र की बैंक शाखाओं में लाभार्थियों की संख्या	ग्रामीण-शहरी महिला लाभार्थियों की संख्या	कुल लाभार्थियों की संख्या
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	22.66	13.54	19.96	36.2
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	7.31	1.14	4.88	8.45
निजी क्षेत्र के बैंक	0.7	0.6	0.71	1.3
कुल	30.67	15.28	25.55	45.95

टिप्पणी: डेटा 6 जुलाई, 2022 तक का है।

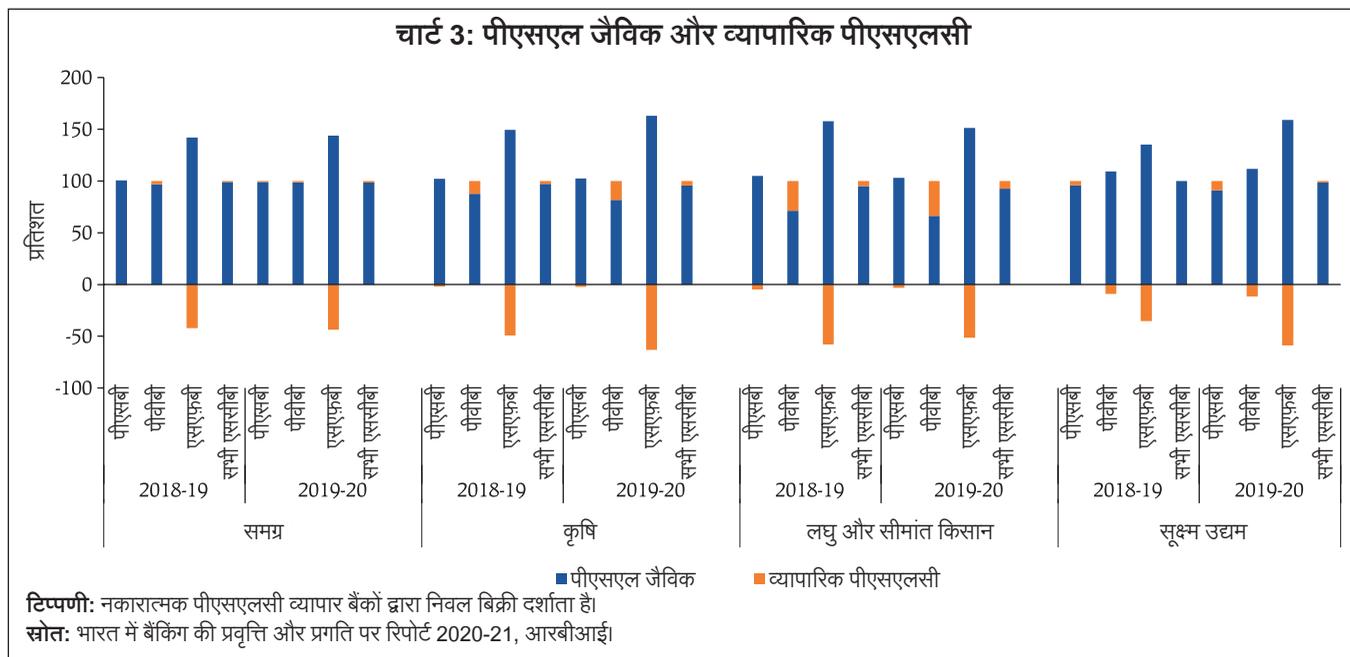
स्रोत: प्रधानमंत्री जन धन योजना, भारत सरकार।

अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पीवीबी 40 प्रतिशत के अपने प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण लक्ष्य को पूरी तरह से पूरा करते हैं और इस प्रकार वित्तीय समावेशन की दिशा में योगदान करते हैं। विस्तृत आंकड़े हालांकि दिखाते हैं कि पीवीबी ने अपने प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लक्ष्यों को मूलभूत उधार के माध्यम से नहीं बल्कि प्राथमिकता क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) में निवेश के माध्यम से पूरा किया है, विशेष रूप से कृषि और छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणियों में। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने की ये श्रेणियां विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण हैं और उच्च प्रीमियम को आकर्षित करती हैं। पीवीबी ने ऐसे ऋण देने में कौशल और विशेषज्ञता विकसित करने के बजाय अपने पीएसएल लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उच्च प्रीमियम का भुगतान करने की इच्छा जताई है।

III. पीएसबी की दक्षता

हम 2010-2022 में भारत में बैंकों के दक्षता स्तरों की जांच करने के लिए डीईए फ्रेमवर्क में इनपुट और आउटपुट के विभिन्न

¹ यद्यपि पीवीबी के पास सूक्ष्म उद्यम श्रेणी में अधिशेष उधार है, जिसका वे पीएसएलसी के माध्यम से व्यापार करते हैं, यह छोटे और सीमांत किसानों के मामले में लगभग 30 प्रतिशत के लक्ष्य घाटे की तुलना में बहुत कम है और कृषि में लक्ष्य घाटे के करीब 20 प्रतिशत के करीब है।



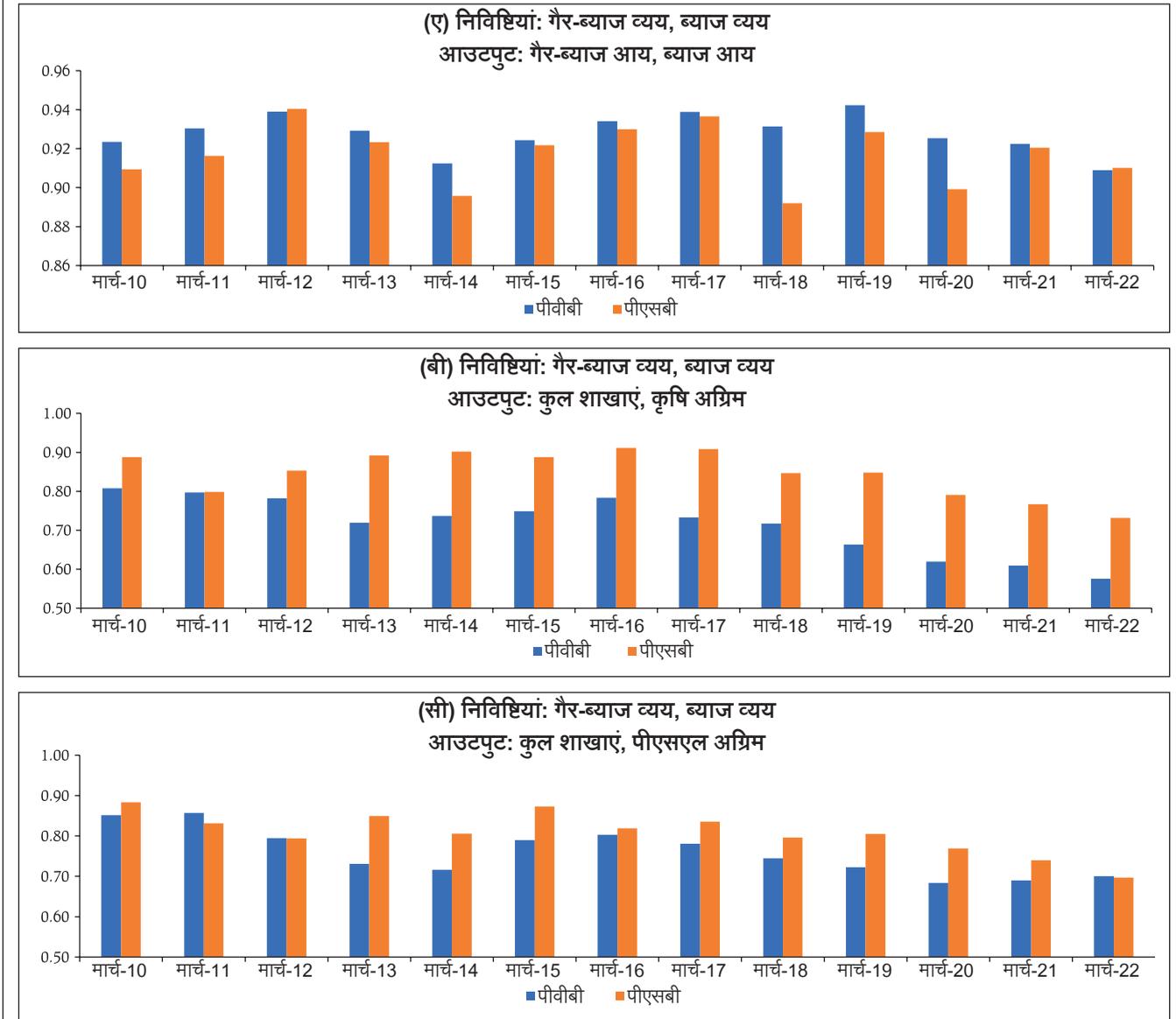
संयोजनों का उपयोग करते हैं। डीईए एक रैखीय-कार्यक्रम-आधारित पद्धति है जो सजातीय संगठनों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए देखे गए इनपुट-आउटपुट अनुपातों की सीमा का निर्माण करती है और बैंकिंग में ज़्यादातर उपयोग की जा रही है (फेयर, ग्रॉसकोफ और लोवेल, 1985)। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली इकाई की दक्षता का एक सारांश माप निकाला जाता है और प्रत्येक निर्णय लेने वाली इकाई (डीएमयू) के प्रदर्शन को इस मानदंड के आधार पर मापा जाता है ताकि यह संकेत मिल सके कि प्रत्येक डीएमयू कितना कुशल या अक्षम है।

अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पीएसबी में कर्मचारी उतने सक्षम नहीं हैं (गुप्ता और पनगढ़िया, 2022)। इस दावे का अनुभवजन्य रूप से मूल्यांकन करने के लिए लागत न्यूनीकरण डीईए फ्रेमवर्क को नियोजित किया गया है। विशेष रूप से, पीवीबी की तुलना में पीएसबी की औसत श्रम लागत दक्षता की तुलना की जाती है। डीईए के इस विशेष रूप में, इनपुट के दिए गए स्तरों, इसकी कीमतों और प्रत्येक इकाई के आउटपुट के लिए, मॉडल सबसे अधिक श्रम लागत-कुशल इकाई की तुलना में प्रत्येक

इकाई के दक्षता स्कोर का अनुमान लगाता है। लागत दक्षता को इस रूप में परिभाषित किया गया है, “दक्षता जो एक माप देती है कि एक बैंक की लागत कितनी करीब है इसके कि समान परिस्थितियों में उत्पादन के समान बंडल का उत्पादन करने के लिए एक सर्वोत्तम अभ्यास बैंक की लागत क्या होगी (कोकिसोवा, 2014)।

कुल जमा, सकल उधार और अग्रिम, कुल निवेश (एसएलआर + गैर एसएलआर) और गैर-ब्याज आय पर डेटा को आउटपुट के रूप में लिया गया जबकि कुल स्टाफ और अचल आस्ति (निवल) को इनपुट के रूप में लिया गया। औसत स्टाफ लागत (कुल स्टाफ लागत/कुल स्टाफ) और किराया, कर, प्रकाश व्यवस्था, बीमा और अचल आस्तियों की प्रति इकाई पर अन्य प्रशासनिक लागत (अन्य परिचालन व्यय/शुद्ध अचल आस्ति) को विश्लेषण के लिए इनपुट कीमतों के रूप में लिया गया। हमारे अध्ययन में बैंकों की संख्या 2010 में 49 और 2022 में 33 के बीच थी। डेटा रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सारणियों के विभिन्न प्रकशनों से प्राप्त किया गया था।

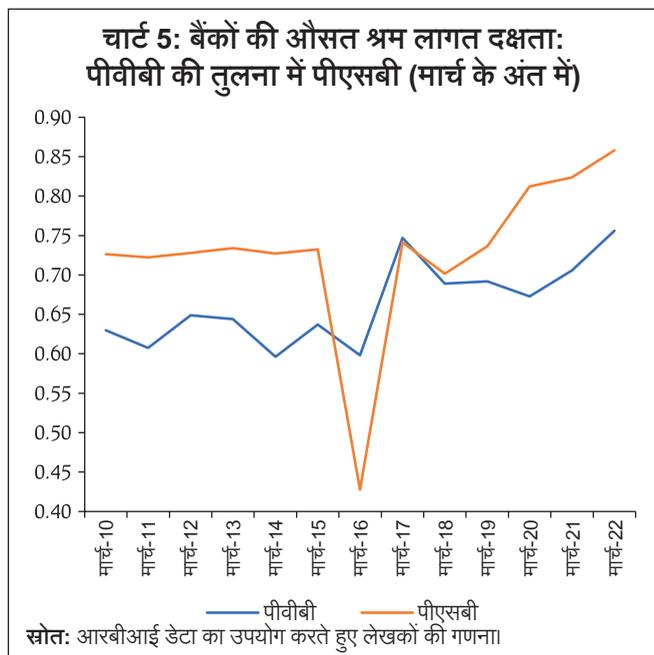
चार्ट 4: पीएसबी और पीवीबी का दक्षता स्कोर: डीईए विश्लेषण



स्रोत: पर्यवेक्षी डेटा के आधार पर लेखकों की गणना।

विश्लेषण से पता चला है कि पीएसबी की श्रम लागत दक्षता 2016 को छोड़कर अधिकांश वर्षों में पीवीबी से अधिक रही है (चार्ट 5)। इसका तात्पर्य यह है कि श्रम पर कम लागत खर्च करके, पीएसबी उच्च स्तर का उत्पादन उत्पन्न कर सकते हैं। यह खोज

पहले के शोध (हेरवाडकर एवं अन्य 2019) के अनुरूप है। बैंकिंग बीसी मॉडल का प्रभावी उपयोग, अन्य लागत-कुशल तकनीकों के कार्यान्वयन के साथ-साथ पीएसबी की उच्च लागत दक्षता के कारण हो सकते हैं।



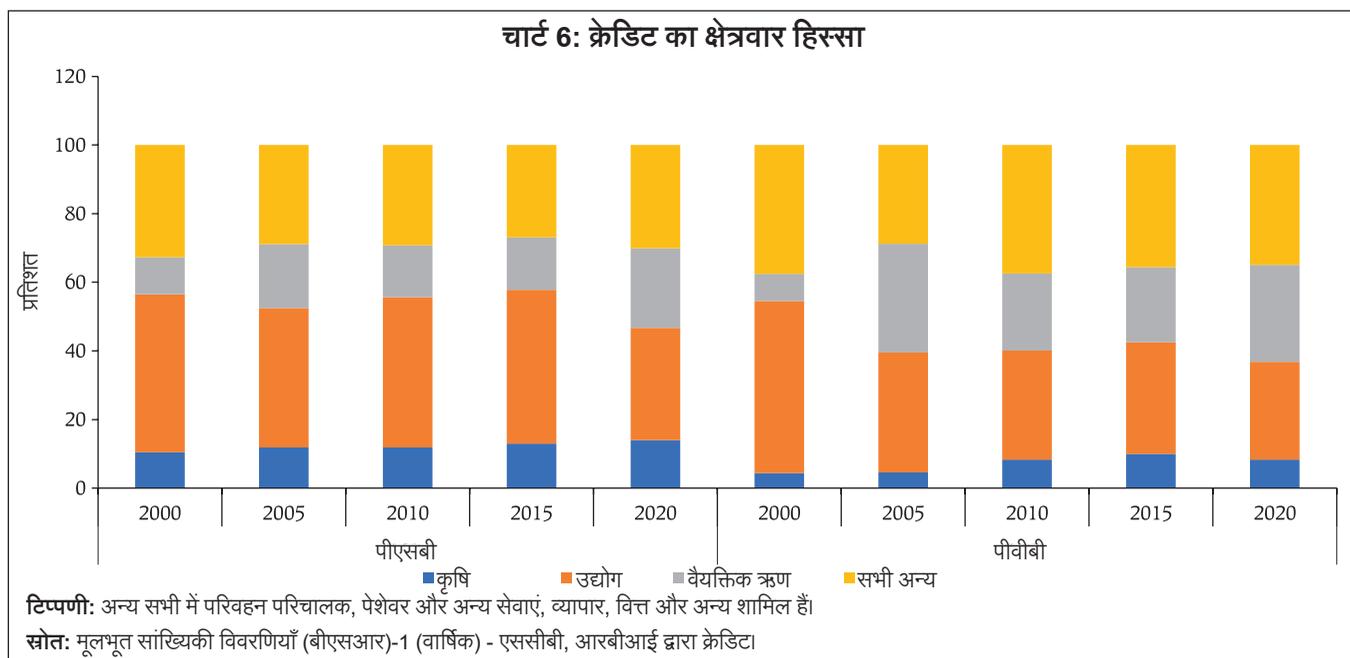
समय के साथ, कृषि ऋण देने में सहकारी बैंकों और आरआरबी की हिस्सेदारी कम हो गई है, जबकि पीएसबी की हिस्सेदारी² बढ़ गई है, यह दर्शाता है कि बाद वाले ने जरूरतमंद क्षेत्र को ऋण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

चूंकि भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार गहरे और जीवंत नहीं हैं, इसलिए उद्योगों के पास संसाधनों को जुटाने के लिए बैंकों की तुलना में कम अन्य रास्ते थे। पहले के शोध से यह भी पता चला है कि बड़े और मजबूत उद्योग इक्विटी बाजार तक आसानी से पहुंच सकते हैं लेकिन यह विकल्प छोटी संस्थाओं के लिए मुश्किल से उपलब्ध है (गांगुली, 2019)। यह 2017-18 से भारतीय अर्थव्यवस्था में शुरू हुए चक्रीय मंदी के दौरान विशेष रूप से सत्य था। औद्योगिक क्षेत्र को ऋण प्रदान करके, पीएसबी ने प्रतिचक्रीय भूमिका निभाई है।

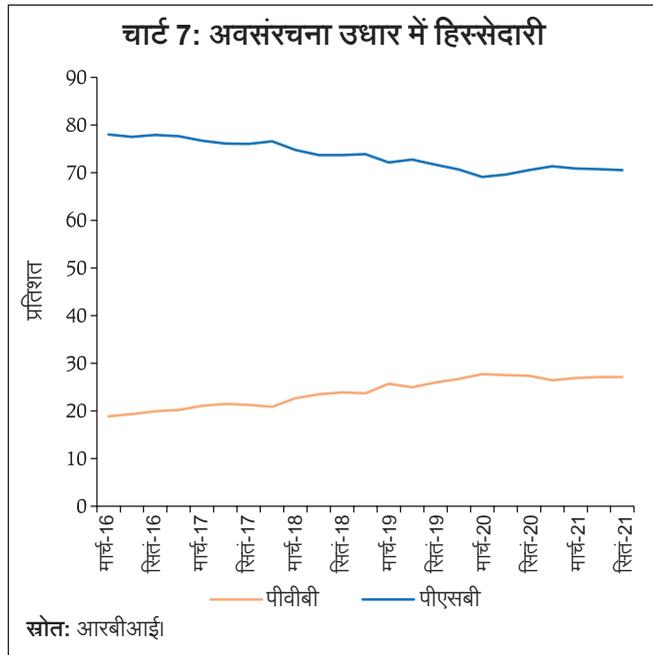
IV: पीएसबी की प्रतिचक्रीय भूमिका

पीवीबी की तुलना में पीएसबी ने लगातार कृषि और उद्योग को अपने कुल ऋण का एक बड़ा हिस्सा आबंटित किया है (चार्ट 6)। कृषि ऋण एक प्राथमिकता है, साथ ही चुनौतीपूर्ण क्षेत्र भी है।

अवसंरचना वित्त देश की संवृद्धि और विकास में एक बाधा रहा है। इन ऋणों में पीएसबी की बड़ी हिस्सेदारी है और उनकी भूमिका पूर्ववर्ती विकास वित्त संस्थानों के खत्म होने के समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही है (चार्ट 7)।



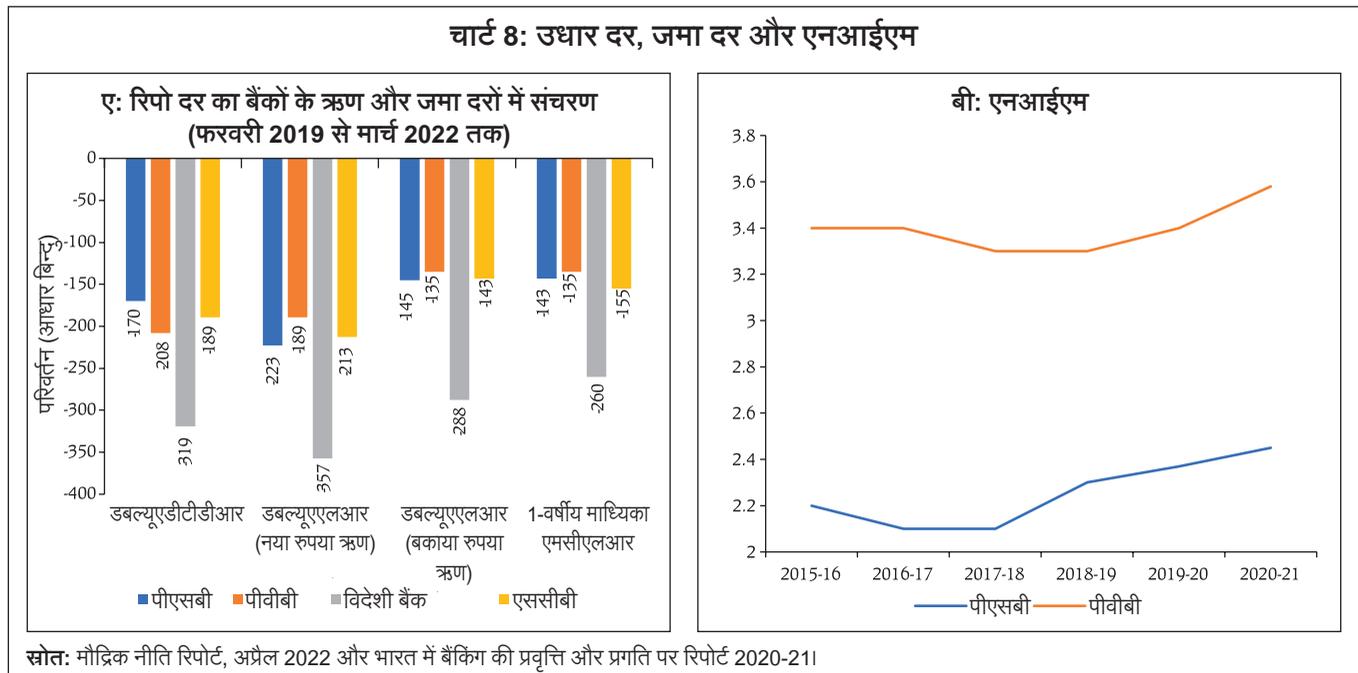
² पीवीबी की कृषि उधार में हिस्सेदारी भी कुछ हद तक बढ़ी है लेकिन प्रगति सुसंगत नहीं है।



पीएसबी मौद्रिक नीति संचरण में भी अधिक प्रभावी हैं, प्रतिचक्रिय मौद्रिक नीति कार्रवाइयों को कर्षण प्राप्त करने में सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए पिछले सहजता चक्र के दौरान, उधार दरों में उनकी कमी पीवीबी की तुलना में काफी अधिक थी (चार्ट 8ए)। साथ ही, पीवीबी की तुलना में उनकी जमा

दरें अपेक्षाकृत स्थिर थीं। पीवीबी के परिणामी उच्च एनआईएम उनके लाभ अधिकतमकरण उद्देश्य का संकेत है (चार्ट 8बी)। दूसरी ओर, मौद्रिक संचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए, पीएसबी ने बड़े सामाजिक लक्ष्यों में योगदान दिया है।

साहित्य सबूतों से भरा पड़ा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तुलना में निजी बैंक उधार देने में अधिक अनुचक्रिय हैं (मार्शल और रोचॉन 2019)। निजी बैंकों द्वारा अनुचक्रिय ऋण प्रतिचक्रिय व्यापक आर्थिक नीतियों की प्रभावशीलता को कम कर सकता है, जबकि राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों द्वारा प्रतिचक्रिय ऋण विशेष रूप से ईएमई में व्यापार चक्र को सुचारू बनाने में उपयोगी हो सकता है, (माइको और पनिज़ा, 2006, विश्व बैंक 2012; ब्रेई और श्वेरेक 2013)। यह जांचने के लिए कि क्या भारत में पीएसबी का उधार अधिक प्रतिचक्रिय (या, विपरीत रूप से, अनुचक्रिय) है, हमने एक निश्चित प्रभाव पैनल प्रतिगमन मॉडल (तालिका 2) में मार्च 2005 से मार्च 2022 की अवधि के लिए 30 बैंकों के तिमाही डेटा का मूल्यांकन किया। आश्रित चर अर्थात् ऋण वृद्धि को आस्तियों के मामले में बैंक के अपने अंतराल और आकार द्वारा समझाया गया है। पीवीबी डमी (पीवीबी = 1) को जीडीपी वृद्धि/जीडीपी वृद्धि के अंतराल के साथ मिलाया जाता है ताकि पीवीबी बनाम पीएसबी के अनुचक्रिय उधार के बीच अंतर का पता लगाया



जा सके। पीवीबी*जीडीपी वृद्धि और पीवीबी*जीडीपी वृद्धि टी-1 के सकारात्मक और महत्वपूर्ण गुणांक यह संकेत देते हैं कि पीवीबी ऋण उनके सार्वजनिक क्षेत्र के समकक्षों की तुलना में अधिक अनुचक्रीय है। इसके अलावा, त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) के नियंत्रण के बाद भी निष्कर्ष मजबूत बने हुए हैं।

V: बाजार विश्वास

वैश्विक वित्तीय संकट की शुरुआत में जमा पीवीबी से पीएसबी में चले गए। एक दृष्टिकोण ने सुझाव दिया कि यह पुनर्आवंटन उस बैंक के बेहतर वित्तीय स्वास्थ्य का संकेत नहीं था, जिससे जमाराशियां गईं, बल्कि उनमें निहित सरकारी गारंटी का संकेत दिया था। शोधकर्ताओं ने तर्क दिया है कि इसका निजी क्षेत्र के बैंकों पर प्रतिकूल और अस्थिर प्रभाव पड़ा है, जहां से उनके बेहतर स्वास्थ्य के बावजूद जमा राशि निकाली गई थी (आइचेनग्रीन और गुप्ता, 2013)।

यस बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक के स्वास्थ्य को लेकर जमाकर्ताओं की चिंताओं के मद्देनजर 2020 की शुरुआत में जमा निकासी की कड़ी के लिए रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध पर्यवेक्षी

डेटा का विश्लेषण- हालांकि अन्यथा सुझाव देता है। इस प्रकरण के दौरान जमा निकासी केवल छोटे निजी बैंकों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि कमजोर वित्तीय स्थिति वाले कुछ पीएसबी को भी इसका सामना करना पड़ा। इन बैंकों द्वारा दूसरों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक ब्याज दरों की पेशकश के बावजूद बहिर्वाह हुआ। जमा आम तौर पर सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में मजबूत बैंकों के पास गए। इससे पता चलता है कि निवेशक और जमाकर्ता अपने विश्वास के मामले में निहित सरकारी गारंटी की तुलना में बैंकों के स्वास्थ्य को अधिक महत्व देते हैं। यह भी तर्क दिया जा सकता है कि ऐसे दबाव की अवधि के दौरान, यदि मजबूत पीएसबी मौजूद नहीं होते, तो बैंकिंग क्षेत्र और अर्थव्यवस्था पर अस्थिरता का प्रभाव बहुत अधिक होता। इस तरह के प्रकरणों से बैंकों पर आसानी से दबाव पड़ सकता था, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय विकेंद्रीकरण हो सकता था। इस लिहाज से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने जनता के विश्वास को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है।

सारणी 3: बैंकों द्वारा निजी आबंटन के माध्यम से जुटाए गए संसाधन

(राशि ₹ करोड़ में)

	2019-20		2020-21		2021-22	
	निर्गमों की संख्या	जुटाई गयी राशि	निर्गमों की संख्या	जुटाई गयी राशि	निर्गमों की संख्या	जुटाई गयी राशि
पीएसबी	20	29,573	36	58,697	29	50,719
पीवीबी	8	23,121	4	33,878	12	35,682

टिप्पणी: कर्ज का निजी आबंटन और योग्य संस्थागत आबंटन शामिल है।

स्रोत: बीएसई, एनएसई और मर्चेंट बैंकर्स।

VI. निष्कर्ष

निजीकरण कोई नई अवधारणा नहीं है, और इसके पक्ष और विपक्ष सर्वविदित हैं। पारंपरिक दृष्टिकोण से कि निजीकरण सभी बीमारियों के लिए रामबाण है, आर्थिक सोच यह स्वीकार करने के लिए एक लंबा सफर तय कर चुकी है कि इसे आगे बढ़ाने के लिए अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता है। यह आलेख साक्ष्य के साथ एक वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रदान करता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पूरी तरह से केवल लाभ अधिकतमकरण लक्ष्य द्वारा

सारणी 2: ऋण वृद्धि का निश्चित प्रभाव पैनल प्रतिगमन

चर	(1)	(2)	(3)	(4)
	ऋण वृद्धि	ऋण वृद्धि	ऋण वृद्धि	ऋण वृद्धि
(ऋण वृद्धि) _{t-1}	0.858*** (0.0189)	0.857*** (0.0193)	0.853*** (0.0206)	0.854*** (0.0203)
लॉग(कुल आस्तियां)	-1.358*** (0.246)	-1.366*** (0.243)	-1.365*** (0.250)	-1.358*** (0.253)
पीवीबी*(जीडीपी वृद्धि) _t	0.130*** (0.0347)			0.131*** (0.0351)
पीवीबी*(जीडीपी वृद्धि) _{t-1}		0.133*** (0.0402)	0.134*** (0.0405)	
पीसीए डमी			-1.109** (0.520)	-1.077** (0.517)
स्थिर	17.12*** (3.114)	17.21*** (3.061)	17.33*** (3.174)	17.24*** (3.226)
बैंक के निश्चित प्रभाव	Yes	Yes	Yes	Yes
अवलोकन	2,036	2,036	2,036	2,036
आर-वर्गित	0.819	0.819	0.819	0.819
बैंकों की संख्या	30	30	30	30

निर्देशित नहीं होते हैं और उन्होंने पीवीबी के विपरीत अपने उद्देश्य कार्य में वांछनीय वित्तीय समावेशन लक्ष्यों को एकीकृत किया है। हमारे परिणाम पीएसबी ऋण देने की प्रतिचक्रिय भूमिका को भी इंगित करते हैं। हाल के वर्षों में, इन बैंकों ने बाजार का अधिक विश्वास भी प्राप्त किया है। कमजोर तुलन पत्र की आलोचना के बावजूद, आंकड़े बताते हैं कि उन्होंने कोविड-19 महामारी के झटकों का उल्लेखनीय ढंग से सामना किया। पीएसबी के हाल के वृहत विलय के परिणामस्वरूप क्षेत्र का समेकन हुआ है, जिससे मजबूत और अधिक प्रतिस्पर्धी बैंक बन गए हैं। राष्ट्रीय आर्स्टि पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल) की स्थापना से उनके तुलन पत्र से खराब ऋणों के पुराने बोझ को हटाने में मदद मिलेगी। हाल ही में गठित अवसंरचना और विकास के वित्तपोषण के लिए राष्ट्रीय बैंक (एनएबीएफआईडी) अवसंरचना वित्त के लिए एक वैकल्पिक चैनल प्रदान करेगा, इस प्रकार पीएसबी की आर्स्टि देयता बेमेल चिंताओं को कम करेगा। कुल मिलाकर, इन सुधारों से पीएसबी को और मजबूत करने में मदद मिलने की संभावना है। इन निष्कर्षों की पृष्ठभूमि में, इन बैंकों के निजीकरण का एक बड़े धमाके का दृष्टिकोण अच्छे से अधिक नुकसान कर सकता है। सरकार पहले ही दो बैंकों के निजीकरण के इरादे की घोषणा कर चुकी है। इस तरह के क्रमिक दृष्टिकोण से यह सुनिश्चित होगा कि बड़े पैमाने पर निजीकरण वित्तीय समावेशन और मौद्रिक संचरण के महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने में एक अंतराल पैदा नहीं करता है।

संदर्भ:

Atkinson, A. B., and Joseph E. Stiglitz. (1980), Lectures on Public Economics, London, Mc-Graw Hill

Cull, R., Peria, M. S., & Verrier, J. (2018). Bank Ownership: Trends and Implications. *World Bank Policy Research Working Paper*.

Brei, M., & Schclarek, A. (2013). Public Bank Lending in Times of Crisis. *Journal of Financial Stability*.

Eichengreen, B., & Gupta, P. (2013). The financial crisis and Indian banks: Survival of the fittest? *Journal of International Money and Finance*.

Estrin, S., & Pelletier, A. (2018). Privatization in Developing Countries: What Are the Lessons of Recent Experience? *World Bank Economic Review*.

Fare, R., Grosskopf, S., & Lovell, C. (1985). The Measurement of Efficiency of Production.

Foray, D., Mowery, D., & Nelson, R. R. (2012). Public R & D and social challenges: what lessons from mission R & D programs.

Ganguly, S. (2019). India's Corporate Bond market: Issues in Market microstructure. *RBI Bulletin, Jaunuary*.

Gupta, P., & Panagariya, A. (2022). Privatization of public sector banks in India- Why, How and How far? *India Policy Forum*.

Herwadkar, S., Neelima, K. M., Verma, R., & Asthana, P. (2019). Labour Cost Efficiency of Indian banks: A Non Parametric Analysis. *RBI Bulletin*.

Kocisova, K. (2014). Application of Data Envelopment Analysis to Measure Cost, Revenue and Profit Efficiency. *Statistika, 94(3)*.

Marois, T. (2021). A Dynamic Theory of Public Banks (And Why It Matters). *Review of Political Economy*.

Marshall, W., & Rochon, L. (2019). Public Banking and Post-Keynesian Economic Theory. *International Journal of Political Economy*.

Mazzucato, M., & Penna, C. (2016). Beyond market failures: the market creating and shaping roles of state investment banks. *Journal of Economic Policy Reforms*.

Micco, A., & Panizza, U. (2006). Bank Ownership and Lending Behaviour. *Economics Letters*.

Panizza, U. (2022). State-owned commercial banks. *Journal of Economic Policy Reform*.

Phukan, S., Punnoose, S. T., Kumar, A., S. D., & Kumar, A. (2021). Financial Inclusion Plans - Reflecting the Growth Trajectory. *RBI Bulletin*.

Schapiro, M. (2012). Rediscovering the developmental path? Development bank, law, and innovation financing in Brazilian economy.

Stiglitz, J. E. (1993). The role of state in financial markets. *The World Bank Economic Review*.

World, B. (2012). Global Financial Development Report 2013: Rethinking the Role of the State in Finance. *World Bank*.